

कृषि और उच्च शिक्षा लागत को नियंत्रित करें : वेंकट्या नायुदू



हैदराबाद, 1 फरवरी-(चन्द्रभान आर.) केन्द्रीय शहरी विकास एवं संसदीय मामलों के मंत्री वेंकट्या नायुदू ने कृषि और उच्च शिक्षा की बढ़ती लागत को नियंत्रित करने के लिए कॉस्ट मैनेजमेंट की आवश्यकता पर जोर दिया।

आज शिल्पकला वेदिका में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउण्टेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के 56वें राष्ट्रीय कॉस्ट अधिवेशन के समापन अवसर पर सभा को सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय मंत्री वेंकट्या नायुदू ने कहा कि बार-बार चुनाव होने के चलते अर्थ-व्यवस्था व जनता को काफी समस्या

हो रही है। अब दिल्ली में चुनाव होने जा रहे हैं। उन्होंने स्थानीय निकाय से लेकर संसद के चुनाव पाँच साल में एक ही बार ही करवाये जाने की आवश्यकता जतायी। सन् 1957 से पूर्व चुनाव सप्ताह के दिनों में हो जाते थे, लेकिन आज कई महीने लग जा रहे हैं।

मंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि स्वच्छ भारत एक लगातार प्रक्रिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे जन आन्दोलन बना दिया है। स्वच्छ भारत बाहर से ही नहीं भीतर से भी हो, ताकि भगवान हमें स्वर्ग में आमंत्रित कर सकें।

शिक्षा के संबंध में केन्द्रीय मंत्री वेंकट्या नायुदू ने कहा कि देश में उच्च शिक्षा की लागत बढ़ती जा रही है। इसके लिए कॉस्ट प्रबंधन की आवश्यकता है। पूर्व की सरकारों के कारण देश की अर्थ-व्यवस्था काफी खराब हो गयी है। देश के विकास को 10 साल की छुट्टी मिल गयी थी। अर्थ-व्यवस्था को मजबूत करने और हानि से उबरने के लिए सभी को साथ मिलकर कार्य करना होगा।

मंत्री ने कहा कि देश की आजादी के बाद 6 दशकों से 57 प्रतिशत जनता के पास बैंकिंग सेवा नहीं थी। अब प्रधानमंत्री की जनधन योजना के अंतर्गत इसमें

उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और आज 11.50 करोड़ जनता ने इस योजना के तहत बैंक खाते खुलवाये हैं। 25 करोड़ परिवारों में से 21 करोड़ के पास बैंक खाता है। इस कार्य को बहुत ही कम समय में पूर्ण किया गया है। मंत्री ने आगे कहा कि वर्ष 2015-16 में विश्व का विकास 3.5 और चीन का 3.7 प्रतिशत है, जबकि देश का विकास 7 प्रतिशत है। भविष्य में भारत विश्व का सातवां आर्थिक विकास का देश बन जायेगा। वर्ष 2025 में देश विश्व का सबसे युवा देश बनेगा, क्योंकि देश में 25 से 35 वर्ष के युवाओं की संख्या लगभग (शेष पृष्ठ 13 पर)